

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ९, अंक ३]

सोमवार, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४

[पृष्ठे ४, किंमत: रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

Order

No. 3/4/ID/2020/SDR(Councils).—Whereas, the Election Commission has been following the policy of compulsory identification of electors by means of specified identification documents at elections to the House of the People and Legislative Assemblies from the year 2000 onwards, so as to prevent impersonation at elections thereby making the right of genuine electors to vote under section 62 of the Representation of the People Act, 1951 more effective; and

- 2. Whereas, keeping in view the provisions of Rules 35(3) and 37(2)(b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission has been issuing directions that the electors at election to House of the People and Legislative Assemblies shall produce their Electors Photo Identity Card or other specified documents at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card or documents may result in the denial of supply of a ballot paper to them and permission to vote; and
- 3. Whereas, the said provisions regarding identification of electors and safeguards against impersonation are equally applicable at elections from Graduates' and Teachers' Constituencies, and as the electors in these constituencies are also electors in assembly constituencies, they would have been supplied with Electors Photo Identity Card as electors in their respective Assembly Constituencies;

- 4. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position the Election Commission hereby directs that all electors at the current (I) Nashik Division Graduates, (II) Amravati Division Graduates', (III) Aurangabad Division Teachers', (IV) Nagpur Division Teachers' & (V) Konkan Division Teachers' Constituencies in the State of Maharashtra and (I) Gorakhpur-Faizabad Division Graduates', (IV) Allahabad-Jhansi Division Graduates' (III) Bareilly-Moradabad Division Graduates', (IV) Allahabad-Jhansi Division Teachers' & (V) Kanpur Division Teachers' Constituencies in the State of Uttar Pradesh, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current biennial elections to the Maharashtra and Uttar Pradesh Legislative Councils from the said Constituencies, notified on 5th January, 2023 (Thursday). However, those electors, who are not able to produce their EPICs, will have to produce any of the following alternative documents for establishing their identity:
 - i. Aadhar Card,
 - ii. Driving License,
 - iii. PAN Card,
 - iv. Indian Passport
 - v. Service Identity Card issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local bodies or other Private Industrial Houses.
 - vi. Official Identity Cards issued to MPs/MLAs/MLCs.
 - vii. Service Identity Card issued by the educational Institutions in which the electors of the concerned Teachers'/Graduates' Constituency may be employed,
 - viii. Certificate of Degree/Diploma issued by University, in original,
 - ix. Certificate of physical handicap issued by competent Authority, in original,
 - x. Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India.

By order,

S. B. JOSHI, Pr. Secretary, Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख: $\cfrac{11$ जनवरी, 2023 $\cfrac{21}{4}$ पौष, 1944 (शक)

आदेश

सं. 3/4/आईडी/ 2020/एसडीआर (परिषद).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान की नीति का अनुसरण करता आ रहा है ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण को रोका जा सके जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और

- 2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2) (ख) के उपबंधों के दृष्टिगत आयोग यह निर्देश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचक मतदान केंद्र पर अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से उक्त निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर या इंकार करने पर उनको मतपत्र प्रदान करने या मत देने की अनुमित दिए जाने से मना किया जा सकता है; और
- 3. यतः, निर्वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के प्रति सुरक्षोपाय से संबंधित उक्त प्रावधान, 'स्नातक' और 'शिक्षक' निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में भी समान रूप से लागू होते हैं और चूंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक होते हैं, इसलिए उन्हें उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदान उपलब्ध कराए गए होंगे;
- 4. अतः, अब, सभी सुसंगत कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निर्देश देता है िक महाराष्ट्र राज्य के (I) नासिक डिवीजन स्नातक, (II) अमरावती डिवीजन स्नातक, (III) औरंगाबाद डिवीजन शिक्षक, (IV) नागपुर डिवीजन शिक्षक एवं (V) कोंकण डिवीजन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश राज्य के (I) गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन स्नातक, (III) कानपुर डिवीजन स्नातक, (III) बरेली-मुरादाबाद डिवीजन स्नातक, (IV) इलाहाबाद-झांसी डिवीजन स्नातक एवं (V) कानपुर डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के सभी निर्वाचकों, जिन्हें एिपक जारी किया गया है, को ५ जनवरी, 2023 (बृहस्पतिवार) को अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चालू द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए इन कार्डों को प्रस्तुत करना होगा। तथािप, ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थािपत करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:—
 - (i) आधार कार्ड;
 - (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स;
 - (iii) पैन कार्ड :
 - (iv) भारतीय पासपोर्ट:
 - (V) राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र :
 - (vi) सांसदों/विधायकों / पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ;
 - (vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र ;
 - (viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र और

8

(x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

भवदीय,

एस. बी. जोशी, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६२/२३/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक : १६ जानेवारी, २०२३

प्रत माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित:

- १. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, नाशिक पदवीधर मतदारसंघ, नाशिक विभाग, नाशिक,
- २. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, अमरावती पदवीधर मतदारसंघ, अमरावती विभाग, अमरावती.
- ३. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघ, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
- ४. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, नागपुर शिक्षक मतदारसंघ, नागपुर विभाग, नागपुर.
- ५. विभागीय आयुक्त व मतदार नोंदणी अधिकारी, कोंकण शिक्षक मतदारसंघ, कोंकण विभाग, मुंबई.
- ६. जिल्हाधिकारी व सहाय्यक मतदान नोंदणी अधिकारी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातुर, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग यांना अग्रेषित.
- ७. उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव,अहमदनगर, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातुर, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग.
- ८. निवड नस्ती.

म. रा. पारकर, उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य.